(ग) इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है ।

आर्थिक-कार्य विभाग में अनुवादकों का कार्य-भार

2854. श्री शिंकरे :
श्री यु० द० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक-कार्य विभाग में काम करने वाले एक हिन्दी अनुवादक को प्रतिदिन कितने शब्दों का अनुवाद करना पड़ता है ;

(ख) क्या आय-व्ययक बनाने के दिनों में तथा उन दिनों में जब आयव्ययक संबंधी काम नहीं होता है प्रत्येक कर्मचारी को उसके दैनिक-कार्य की अपेक्षा कम काम दिया जाता है ; और

(ग) जब अनुवादक का कोई कार्य नहीं होता है तब हिन्दी के कर्मचारियों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

वित्त मंत्री श्री (शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). अनुवाद का मापदण्ड इस समय 1000 शब्द प्रतिदिन है, यद्यपि इससे कुछ भिन्न मापदण्ड निर्धारित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है । मापदण्ड कुछ भी हो, यह केवल कर्मचारियों की आवश्यक संख्या का सम्पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के लिए ही प्रासंगिक होता है । काम की वास्तविक मात्रा के कारण, जो बहुत असमान रहती है और बजट के दिनों में खासतौर से बहुत बढ़ जाती है, सामान्य अधिकारियों को न केवल समयोपरि (ओवर टाइम) काम करना पड़ता है, बल्कि काम की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में अस्थायी रूप से वृद्धि भी करनी पड़ती है । जब काम का भार कम हो जाता है, तो अस्थायी रूप से बढ़ाये गये कर्मचारी वापस ले लिए जाते हैं । जिस अवधि में काम कम रहता है, उसमें भी सामान्य कर्मचारियों के लिए काफी काम रहता है, लेकिन जहां तक सम्भव होता है उनमें से कुछ कर्मचारियों को दूसरा काम भी सौंपा जाता है ।

Housing Plans for Mysore

2855. Shri H. C. Linga Reddy: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the amount provided for Housing in the Third Plan in the State of Mysore;

(b) the amount actually spent and the names of the schemes for which spent;

(c) the reasons for shortfall in expenditure;

(d) the amount proposed to be spent in the Fourth Plan period; and

(e) the extent to which the needs of the people for housing have been met?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-7479/66].

(c) The shortfall is mainly due to the low priority given by the State Government to housing schemes, as compared to projects like Power, Irrigation, Agriculture etc.

(d) The Working Group on Housing and Urban Development for Mysore has recommended an outlay of Rs. 600.00 lakhs from Plan funds for implementation of the various housing schemes in the State in the Fourth Five Year Plan. The amount of the Non-Plan funds is, however, not known at present, as the Life Insu-